

(iv) एम.एन. गोविंदन नायर नं० 77, प्रसाद नगर (मध्यम श्रेणी वर्ग) फ्लटस ।

(v) राजीव गांधी राष्ट्रीय निवेश बैंक के माध्यम से एम.एन. गोविंदन नायर फ्लटस की-8 सेक।

(ग) जी नहीं, क्योंकि राशि कहीं अन्य फ्लटों की लागत बढ़ाने में प्रयोग में लाई गई थी।

भारतीय खाद्य निगम, मुरादाबाद द्वारा सरकार को संपादित की गयी टेंडर का निम्नलिखित किस्म कागज

4698. श्री सुजित सिंघु बरनाला : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) ने अप्रैल, 1978 में सरकार को संपादित किए गए टेंडर प्रामाणिक किये थे ;

(ख) इसके लिए कितने टेंडर प्राप्त हुए और उनमें से कितने टेंडर हस्ताक्षर युक्त थे, और क्या वे कम दर वाले टेंडर भेजने वाले व्यक्तियों के नाम क्या थे—और

(ग) क्या इस मामले में बीटाब्लि के बारे में भारतीय खाद्य निगम, मुरादाबाद के जिला मनेजर को अभ्यावेदन दिये गये थे और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई विभाग में राज्य मंत्री (श्री कानू अताब सिंह) : (क) 1977-78 और 1978-79 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने मुरादाबाद जिला (उत्तर प्रदेश) में सरकार द्वारा जल की संपादित किए गए टेंडर प्रामाणिक नहीं किए थे।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Financial aid for crop cultivation in Kerala

4699. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any financial assistance has been sought for launching a comprehensive programme for extension of cultivation of Coco in Kerala from the Centre;

(b) what are the details of the projects; and

(c) Union Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) The scheme for development of Cocoa envisages cultivation of cocoa in 25000 ha. as an inter crop in coconut and arecanut gardens during a period of 7 years from 1978-79 with an estimated cost of Rs. 71.532 lakhs. During 1978-79 the expenditure is estimated at Rs. 7.838 lakhs. The State Government have asked for Central assistance and have requested to sanction the scheme as a Centrally Sponsored one.

(c) The Government of India is already assisting the State Government for establishing an 8 ha Cocoa seed garden under the Centrally Sponsored Scheme and has sanctioned a sum of Rs. 3.138 lakhs for three years from 1976-77.

With regard to the request now received from the State Government, it was told that further assistance for Cocoa development programmes during 6th Plan is yet to be analysed and as soon as the Planning Commission approves the 6th Plan Programme and the pattern of assistance for various crops, the State Government will be informed of the extent to which Government of India can render assistance for the scheme. The State